(b) if so, the details of the estimated losses to various sectors; and

(c) whether Government have released the first instalment as announced by the Hon'ble Prime Minister in Hyderabad after visiting the effected areas?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) and (b) A Central Team which visited Andhra Pradesh for assessment of the situation in the wake of heavy rains/floods submitted its report which is now to be considered by the National Calamity Relief Committee (NCRC), the authority which ultimately, decides the quantum of assistance, if any, to be provided from the National Fund for Calamity Relief (NFCR).

(c) The Advance Plan assistance of Rs. 200 crore announced by the Prime Minister has already been released to the Government of Andhra Pradesh.

Schemes for the benefit of small and marginal Farmers

1244. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the details of the schemes in operation for the benefit of small and marginal farmers;

(b) how far they have progressed during the last two years; and

(c) how many small and marginal farmers have been benefited by these schemes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) to (c) There are no separate schemes only for the small and marginal farmers. A number of Centrally Sponsored Scheme are being implemented for development of agriculture which benefit all categories of farmers including small and marginal farmers. According to the Agricultural Census 1990-91, small and marginal farmers account for 78 per cent of operational holdings. Selection of beneficiary farmers is done by the State Government and they have been advised to give priority to small and marginal farmers while selecting the beneficiaries.

सरकारी क्षेत्र में उन्नत बीजों का उत्पादन

1245. **श्री कपिल सिब्बल:**
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के सरकारी क्षेत्र में प्रामाणिक व उन्नत बीजों का उत्पादन होता है;

(ख) यदि हां, तो कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है और इनकी खाद्यान्न-वार मात्रा कितनी-कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने इन संस्थानों द्वारा उत्पादित बीजों की औसत वार्षिक मात्रा का अनुमान लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो किस-किस खाद्यान्न का कितना-कितना बीज औसतन वार्षिक रूप से पैदा किया जाता है और यह मात्रा देश की वार्षिक आवश्यकताओं से कितनी कम होती है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) सार्वजनिक क्षेत्र में प्रमाणित और उन्नत गुणवत्ता प्राप्त बीजों का उत्पादन राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बीज निगम तथा भारतीय राज्य फार्म निगम द्वारा तथा राज्य स्तर पर राज्य बीज निगमों, राज्य सरकार के बीज फार्मों, कृषि-उद्योग निगमों तथा सहकारी संस्थाओं आदि द्वारा किया जाता है।

(ख) से (घ) 1996-97, 1997-98 और 1998-99 के दौरान देश में अनाजों और दलहनों के लिए प्रमाणित/गुणवत्ता प्राप्त बीजों की मांग और उपलब्धता दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

अनाजों तथा दलहनों के संबंध में प्रमाणित/गुणवत्ता प्राप्त बीज की मांग तथा उपलब्धता

(लाख क्विंटल)

क्रम सं॰	फसल	1996-97		1997-98		1998-99	अनुमानित
		मांग	उपलब्धता	मांग	उपलब्धता	मांग	उपलब्धता
1.	गेहूं	25.24	26.20	25.58	28.04	28.09	30.33
2.	धान	18.27	25.80	19.64	27.44	22.79	30.30
3.	मक्का	1.63	2.04	2.00	2.92	2.32	3.17
4.	ज्वार	3.26	5.45	3.16	5.88	3.05	5.66
5.	बाजरा	1.68	2.49	1.75	3.35	1.58	3.77
6.	अन्य	0.30	0.44	0.32	0.34	0.39	0.58
	सभी अनाज	50.38	62.42	52.45	67.97	58.22	73.81
7.	चना	1.82	1.83	1.63	1.45	1.77	1.71
8.	मसूर	0.17	0.12	0.14	0.16	0.24	0.24
9.	मटर	0.41	0.36	0.44	0.45	0.41	0.41
10.	उड़द	0.98	1.39	1.26	1.66	1.30	1.27
11.	मूंग	0.78	1.31	0.92	1.37	0.92	1.34
12.	अरहर	0.71	0.67	0.71	0.77	0.69	0.90
13.	अन्य	0.19	0.17	0.15	0.10	0.14	0.14
	सभी दलहन	5.06	5.85	5.25	5.96	5.47	6.01

दिल्ली दुग्ध योजना को घाटा होना

1246. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:
श्री कपिल सिब्बल:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा उत्पादित दूध दिल्ली राज्य के आम आदमी को बेचा जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि जिस कीमत पर दूध का उत्पादन किया जाता है उसकी बिक्री से उतना दाम भी नहीं वसूला जाता; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली दुग्ध योजना को औसतन एक माह में कितना घाटा उठाना पड़ता है और इस घाटे के क्या-क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा उत्पादित दूध की बिक्री दिल्ली राज्य के आम लोगों के लिए की जाती है। इसके अलावा इसे दिल्ली राज्य के सरकारी और गैर-सरकारी अस्पतालों तथा संस्थानों को भी बेचा जाता है।

(ख) और (ग) दूध की बिक्री से वसूल की गई राशि दूध के उत्पादन पर खर्च की गई लागत से कम है क्योंकि दूध का बिक्री मूल्य उत्पादन लागत से काफी कम है। टोण्ड दूध और डबल टोण्ड दूध की मौजूदा उत्पादन लागत (अप्रैल-अक्तूबर, 1998 के दौरान) क्रमशः 12.73 रुपये प्रति लीटर और 11.48 रुपए प्रति लीटर है जबकि टोण्ड दूध की बिक्री मूल्य प्रति लीटर 7 रुपए है और डबल टोण्ड का बिक्री मूल्य प्रति लीटर 6